



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 23 अगस्त, 2006/1 भाद्रपद, 1928

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 23 अगस्त, 2006

संख्या वि०स०-विधायन-गवर्न० बिल०/1-45/2006.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पथकर

(संशोधन) विधेयक, 2006 (2006 का विधेयक संख्यांक 18) जो आज दिनांक 23-8-2006 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

जे० आर० गांजटा,
सचिव ।

राज्यपाल
हिमाचल प्रदेश
श्री जे. आर. गांजटा
सचिव

हिमाचल प्रदेश पथकर (संशोधन) विधेयक, 2006

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का 9) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पथकर (संशोधन) अधिनियम, 2006 है । संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) यह 23 मई, 2006 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

9 2. हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 की धारा 9 के पश्चात् धारा 10, निम्नलिखित धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:- 10-क और 10-ख का अन्तःस्थापन।

"10. प्रतिदाय.—सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला का भारसाधक आबकारी एवं कराधान अधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या आवेदन पर, पट्टेदार या किसी अन्य व्यक्ति को आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से ऐसे पट्टेदार या व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन संदत्त पट्टा धन की किसी भी रकम का विहित रीति में प्रतिदाय करेगा, यदि इस प्रकार संदत्त पट्टा धन की रकम, इस अधिनियम के अधीन उस द्वारा देय रकम से अधिक है:

परन्तु यह कि प्रतिदाय विधि और व्यवस्था की स्थिति, प्राकृतिक विपत्ति या दैवकृत्य या अनिवार्य वाध्यता के कारण हुई किसी भी हानि की दशा में ही अनुज्ञात किया जाएगा :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन कोई भी प्रतिदाय तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रतिदाय के लिए दावा, उस तारीख से, जिस को कि ऐसा दावा प्रोदभूत होता है, एक वर्ष की अवधि के भीतर न किया गया हो ।

10-क. अपील.—इस अधिनियम के अधीन पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अपील प्राधिकारी को, ऐसे आदेश के पारित करने के साठ दिन के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर जिसे अपील प्राधिकारी पर्याप्त हेतुक के अनुज्ञात करे, होगी।

10-ख. पुनरीक्षण.—आयुक्त स्वप्रेरणा से, किसी भी कार्यवाही, जो उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है या उसके द्वारा निपटाई गई हैं, का अभिलेख ऐसी कार्यवाहियों की वैधता और औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए मंगवा सकेगा या आदेश राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है तो उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे:

परन्तु इस धारा के अधीन शक्तियां उस तारीख से जिसको कि ऐसा आदेश संसूचित किया गया था पांच वर्ष की अवधि के भीतर ही प्रयोक्तव्य होंगी।”।

3. (1) हिमाचल प्रदेश पथकर (संशोधन) अध्यादेश, 2006 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

2006 के
अध्यादेश
संख्यांक 1 का
निरसन और
व्यावृत्तियां।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 में अपील, पुनरीक्षण तथा प्रतिदाय के लिए कोई उपबन्ध नहीं है, जबकि अन्य कराधान विधियों जैसे कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 में कर, यदि देय रकम से अधिक संदत्त किया गया है, के प्रतिदाय हेतु, अपील तथा पुनरीक्षण के लिए उपबन्ध है। कराधान विधियों को तर्कसंगत बनाने तथा उनमें एकरूपता लाने के लिए पट्टा धन, यदि देय रकम से अधिक संदत्त किया गया है, के प्रतिदाय हेतु अपील तथा पुनरीक्षण के उपबन्धों को उपर्युक्त अधिनियम में सम्मिलित किया जाना समुचित समझा गया। इसलिए उपर्युक्त अधिनियम में संशोधन किए जाने आवश्यक हो गये हैं।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का 9) में तुरन्त संशोधन करना अपेक्षित हो गया था, इसलिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश पथकर (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (2006 का अध्यादेश संख्यांक 1) तारीख 18-5-2006 को प्रख्यापित किया गया और जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में 23-5-2006 को प्रकाशित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के प्रतिस्थापित करने के लिए है।

रंगीला राम राव,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला:

तारीख....., 2006.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2, सहायक आबकारी एवम् कराधान आयुक्त तथा जिला के भारसाधक आबकारी एवं कराधान अधिकारी को, आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से, पट्टेदार को पट्टाधन, यदि देय रकम से अधिक संदत्त किया गया है, के प्रतिदाय के लिए सशक्त करता है। विधेयक के उपबन्धों के अधिनियमित होने से सरकार के राजस्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2, राज्य सरकार को, उस प्रक्रिया और रीति, जिसमें कि पट्टेदार या किसी अन्य व्यक्ति को जिसने उस द्वारा देय रकम से अधिक पथकर संदत्त किया है प्रतिदाय किया जाना है, का उपबन्ध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[नस्ति संख्या ई.एक्स.एन.-एफ(10)1/2005 पी.एफ.]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पथकर (संशोधन) विधेयक, 2006 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

Bill No. 18 of 2006.

THE HIMACHAL PRADESH TOLLS (AMENDMENT) BILL, 2006

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975 (Act No. 9 of 1975)

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Tolls (Amendment) Act, 2006.

Short title and commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force on 23rd day of May, 2006.

2. After section 9 of the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975, the following sections shall be inserted, namely:—

Insertion of sections 10, 10-A and 10-B.

“10. Refund.— The Assistant Excise and Taxation Commissioner or the Excise and Taxation Officer incharge of the district either *suo moto* or on an application shall, in the prescribed manner, refund to the lessee or any other person, with the prior approval of the Commissioner, any amount of lease money paid by such lessee or person under this Act, if the amount of lease money so paid is in excess of the amount due from him under this Act:

Provided that refund shall only be allowed to the lessee in the event of any loss sustained on account of law and order situation, natural calamity or by acts of God or force majeure:

Provided further that no refund under this section shall be allowed unless the claim for refund is made within a period of one year from the date on which such claim accrues.

10-A. Appeal.—An appeal shall lie to the appellate authority, appointed by the State Government in this behalf, against any order passed under this Act, within sixty days of the passing of such order or within such further period as the appellate authority may, for sufficient cause, allow.

10-B. Revision.—The Commissioner may, of his own motion, call for the record of any proceeding which is pending before, or have been disposed of by any authority subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of such proceedings or the orders are prejudicial to the interest of revenue, may pass such order in relation thereto as he may think fit:

Provided that powers under this section shall be exercisable only within a period of five years from the date on which such order was communicated.

Repeal of
Ordinance No.
1 of 2006 and
savings.

3. (1) The Himachal Pradesh Tolls (Amendment) Ordinance, 2006 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There are no provisions of appeal, revision and refund in the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975, whereas other taxation laws such as the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, provides for refund of tax if paid in excess of the amount due and provisions of appeal and revision. In order to rationalize and to bring uniformity in taxation laws, it was considered appropriate to incorporate provisions of refund of lease money if paid in excess of the amount due and provisions of appeal and revision in the Act *ibid*. This has necessitated amendments in the Act *ibid*.

Since the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the amendment in the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975 (Act No. 9 of 1975) was required to be carried out urgently, therefore, the Governor, Himachal Pradesh promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Himachal Pradesh Tolls (Amendment) Ordinance, 2006 (Ord. No. 1 of 2006) on 18-5-2006 and the same was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on 23-5-2006. Now, the said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance without any modification.

RANGILA RAM RAO,
Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The....., 2006.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 of the Bill seeks to empower the Assistant Excise and Taxation Commissioner and the Excise and Taxation Officer incharge of the district, to refund amount of lease money, if paid in excess of the amount due with the prior approval of the Commissioner to the lessee. The provisions of the Bill, if enacted, shall not have any adverse impact on the Government revenue and there will be no additional expenditure out of the State Exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 2 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules providing for the procedure and manner in which the refund is to be made to the lessee or any other person who have paid toll in excess of the amount due from him.

**RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE
CONSTITUTION OF INDIA**

[Excise Deptt. File No. EXN-F(10)-1/2005-PF]

Governor of Himachal Pradesh after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Tolls (Amendment) Bill, 2006, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill by the Legislative Assembly.